डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 अगस्त, 2020, डिस्पेच दिनांक 1 अगस्त, 2020

| वर्ष 64 | अंक 05 | भोपाल | 1 अगस्त, 2020 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/– | आजीवन शुल्क 1500/– |

सहकारिता मंत्री श्री अरविन्द भदौरिया ने कार्यभार ग्रहण किया

भोपाल। श्री अरविन्द भदौरिया ने मंगलवार को सहकारिता एवं लोक प्रबंधन मंत्री का कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व उन्होंने विधिवत पूजा–अर्चना की। इस अवसर पर सांसद श्री रमाकांत भार्गव के अलावा श्री सुभाष भाड़गे, श्री किशन सिंह भटोल, श्री विवेक चतुर्वेदी, श्री शिवनारायण पाटीदार, श्री उमा नारायण, श्री संजीव कांकर, श्री मोहित शुक्ला, श्री हरीश शर्मा, श्री आशीष भदौरिया, श्री सुनील सिंह भदौरिया, श्री कुलदीप ठाकुर, श्री भरत सिंह व अन्य लोग उपस्थित थे।

परिचय

डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया का जन्म 9 अगस्त, 1968 को हुआ। उन्होने एम.ए., एल.एल.बी., और पीएचडी तक शिक्षा प्राप्त की।

डॉ. भदौरिया दस वर्ष तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। 1987 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् भिण्ड के नगर अध्यक्ष, 1988 में एम.जे.एस. कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, 1990–95 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री एवं 1995–2003 में प्रदेश संगठन मंत्री रहे। सन् 2003–2004 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश संगठन मंत्री एवं 2004–2005 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 2005 से पांच बार भा.ज.पा मध्यप्रदेश के प्रदेश मंत्री, महामंत्री भा.ज.पा. और मध्यप्रदेश अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन से संबद्ध रहकर बस्तियों में संस्कार केन्द्रों, स्वास्थ्य शिविरों और युवा गतिविधियों का संचालन किया। उन्होंने विश्वविद्यालय संशोधन के विरोध में आंदोलन एवं जेल यात्रा की। डॉ. भदौरिया उपाध्यक्ष भा.ज.पा मध्यप्रदेश तथा रेडक्रास सोसाइटी मध्यप्रदेश इकाई के वाइस प्रेसीडेंट भी हैं। सन् 2008 में तेरहवीं विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए।

डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया सन् 2018 में दूसरी बार भिण्ड जिले की अटेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। डॉ. भदौरिया ने 2 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्री–मण्डल में मंत्री पद की शपथ ग्रहण की।

संस्थाओं में गबन व धोखाधड़ी करने वाले प्रबंधकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही हो

मंत्री श्री भदौरिया ने विभागीय अधिकारियों की ली बैठक

भोपाल। सहकारिता एवं लोकसेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविन्द भदौरिया ने पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक ली। बैठक में मंत्री श्री भदौरिया ने सहकारिता विभाग के कार्यों व गतिविधियों के संबंध में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि सहकारी संस्थाओं में गबन व धोखाधड़ी करने वाले समिति प्रबंधकों के विरुद्ध ऐसी कड़ी कार्यवाही हो जो दूसरो के लिये नजीर बने।

मंत्री श्री भदौरिया ने कहा कि सिस्टम में हर स्तर पर पारदर्शिता से काम किये जाये। ऐसे प्रावधान किये जाएं ताकि गडबड़ी की गुंजाईश न हो। उन्होंने हरदा जिले में चना उपार्जन में समिति प्रबंधक द्वारा अनियमितता बरतने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कठोर वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिये। आयुक्त सहकारिता श्री आशीष सक्सेना ने विभाग की गतिविधियों से अवगत कराते हुए बताया कि विभाग द्वारा संस्थाओं के पंजीयन व अंकेक्षण से संबंधित कार्य किया जाता है। संस्थाओं के प्रशासकीय नियंत्रण एवं नियमन के लिये नियम बनाने के साथ ही अन्य कार्य भी विभाग द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। विभाग द्वारा एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएँ भी संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा संस्थाओं के माध्यम से कृषि ऋण उपलब्ध कराने व खाद्य विभाग के अन्तर्गत खाद्यान्न उपार्जन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य सहकारिता विभाग द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

मंत्री श्री भदौरिया ने मार्कफेड व बीज संघ की गतिविधियों की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग से समन्वय कर ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज व उर्वरक उपलब्ध हो। उन्होंने नकली बीज व उर्वरक विक्रय करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये। बैठक में दुग्ध संघ, लघु वनोपज संघ, मत्स्य उत्पादन संघ की गतिविधियों से अवगत कराया गया। बैठक में अपर आयुक्त सहकारिता श्री अरूण माथुर, संयुक्त आयुक्त श्री अरविन्द सेंगर, सचिव विपणन संघ श्री पी.एस. तिवारी, उप सचिव सहकारिता श्री मनोज सिन्हा मौजूद थे।

केंद्रीय क्षेत्र योजना

'कृषि अवसंरचना कोष' के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा

नई दिल्ली। कृषि अवसंरचना कोष की यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से, फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम–लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी।

इस योजना के अंतर्गत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा एक लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसी), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (जेएलसी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअपों, संग्रहित अवसंरचना प्रदाताओं और केंद्रीय/राज्य एजेंसियों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनों को उपलब्ध कराई जाएगी। ऋण का वितरण चार वर्षों में किया जाएगा, चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और अगले तीन वित्तीय वर्ष में 30,000 करोड़ रुपये क्रमशः की मंजूरी प्रदान की गई है।

इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत, सभी प्रकार के ऋणों में प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये की सीमा तक ब्याज में 3ः की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) योजना के अंतर्गत इस वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। इस कवरेज के लिए सरकार द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। एफपीओ के मामले में, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएफडब्ल्यू) के एफपीओ संवर्धन योजना के अंतर्गत बनाई गई इस सुविधा से क्रेडिट गारंटी का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

भारत सरकार की ओर से बजटीय सहायता के रूप में कुल बहिर्गमन 10,736 करोड़ रुपये का होगा। इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष के लिए हो सकता है। कृषि और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा के माध्यम से, इस परियोजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न होने की संभावना है।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सूचना

कोविड-19 के कारण हुए लाकडाउन की वजह से मध्यप्रदेश सहकारी समाचार का यह अंक ई-सहकारी समाचार के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

मैं किसानों का वंदन तथा हमारे अमले का अभिनंदन करता हूँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में गेहूँ के रिकॉर्ड उपार्जन के लिए प्रदेश के किसान एवं संबंधित विभाग बधाई के पात्र हैं। कोरोना जैसे संकट के समय में जहाँ उपार्जन एक बहुत बड़ी चुनौती थी, प्रदेश के किसानों तथा हमारी मशीनरी ने यह दिखा दिया है कि अगर दिल में काम करने का जज्बा हो तो कोई कार्य कठिन नहीं है। इसके लिए मैं प्रदेश के किसानों का वंदन तथा हमारे अमले का अभिनंदन करता हूँ।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे थे, जिन्होंने समर्थन मूल्य पर अपना गेहूँ विक्रय किया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ किसानों एवं समिति प्रबंधकों से चर्चा भी की। इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिव शेखर शुक्ला उपस्थित थे।

आप सभी के सहयोग से गेहूँ का रिकॉर्ड उपार्जन

मुख्यमंत्री चौहान ने किसानों से कहा कि आप सभी के सहयोग से प्रदेश में गेहूँ का ऑल टाइम रिकॉर्ड उपार्जन हुआ है। गेहूँ उपार्जन में मध्यप्रदेश देश में नंबर वन रहा है। इस बार गेहूँ का उपार्जन एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बारदाने की कमी होने से हमने प्लास्टिक के बैग इस्तेमाल किए। खरीदी केंद्रों को बढ़ाकर साढ़े चार हजार से अधिक किया गया। एसएमएस के माध्यम से किसानों को सूचना दी गई। एक बड़ी समस्या किसानों का चमक विहीन गेहूँ था। इस संबंध में केंद्र सरकार से अनुमति लेकर किसानों का चमक विहीन गेहूँ भी खरीदा गया। अधिक उपार्जन के कारण भंडारण की भी समस्या थी। सरकार द्वारा 3 माह का इकट्ठा गेहूँ राशन में वितरित किया गया। सबसे पहले छोटे एवं मझोले 9 लाख 27 हजार किसानों को गेहूँ विक्रय के लिए बुलाया गया। किसानों ने भी पूरे अनुशासन एवं सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपना गेहूँ समर्थन मूल्य पर बेचा और हमने देश में रिकॉर्ड कायम किया।

शानदार थी इस बार की खरीदी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंदसौर जिले के किसान प्रदीप सिंह, रीवा के वीरेंद्र सिंह, मुरैना के दोजी राम जाटव, हरदा की सुशीला जी, सागर के उधम सिंह, शहडोल के रामजी सिंह राजपूत, रायसेन के शेख मौज्जम तथा अलीराजपुर के किसान श्री भैरव सिंह से बातचीत की। सभी ने बताया कि इस बार गेहूँ खरीदी की शानदार व्यवस्था थी। सूचना मिलने पर उपार्जन केंद्र पर गए, वहाँ बहुत कम समय में हमारा गेहूँ तुल गया तथा सबसे बड़ी बात तो यह है कि 7 दिन के अंदर हमें अपने गेहूँ का भुगतान भी प्राप्त हो गया। हमने अपनी जिंदगी में इतनी अच्छी व्यवस्था कभी नहीं देखी। इसके लिए उन्होंने हृदय से मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार व्यक्त किया।

उप केंद्र बनाने से व्यवस्थाएं आसान हुई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने होशंगाबाद जिले की सांवलखेड़ा सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक श्री सुरेश कुमार वर्मा तथा सीहोर जिले की हमीदगंज कृषि साख सहकारी समिति के प्रबंधक श्री अशोक शर्मा से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि इस बार बड़ी संख्या में उप केंद्र खोले जाने से खरीदी में बहुत सुगमता हुई। आगे भी इस व्यवस्था को जारी रखा जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि उपार्जन केंद्रों पर गोदाम भी बनाए जाने चाहिए जिससे कि भंडारण में सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री निरंतर किसानों के हित में कार्य करते हैं

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से चर्चा के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान लगातार किसानों के हित में कार्य करते हैं तथा उन्हें हमेशा किसानों की चिंता रहती है। प्रदेश में गेहूँ का उपार्जन निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कार्य है। कोरोना जैसी महामारी के होते हुए भी जिस प्रकार सभी के सहयोग से पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ गेहूँ खरीदी का कार्य हुआ है वह अभूतपूर्व है। सबसे बड़ी उपलब्धि है किसानों को उनकी फसल का समय पर भुगतान भी हुआ है।

- रबी विपणन वर्ष 2020–21 में 15.80 लाख किसानों से 129.34 लाख मे.टन गेहूँ उपार्जन कर देश में अधिकतम गेहूँ उपार्जन वाला राज्य।
- देश में कुल 388.34 लाख मे. टन गेहूँ का उपार्जन हुआ है, जिसमें मध्यप्रदेश द्वारा 33 प्रतिशत योगदान रहा है।
- उपार्जन के लिये लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर एस.एम.एस. प्रेषित कर 9.27 लाख लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा गेहूँ का विक्रय किया गया है।
- वन क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के पट्टाधारी किसानों का पंजीयन पृथक श्रेणी में किया गया।
- एस.एम.एस. के माध्यम से कृषकों को खरीदी दिनांक की जानकारी दी गई।

हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिये कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं। विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं।

–स्वामी विवेकानंद

(पृष्ठ 1 का शेष)

'कृषि अवसंरचना कोष' के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा

कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबन्धान सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। यह सभी योग्य संस्थाओं को फंड के अंतर्गत ऋण लेने के लिए आवेदन करने का पात्र बनाएगा। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की तीव्र प्रक्रिया के साथ–साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान करेगा।

सही समय पर मॉनिटरिंग और प्रभावी फीडबैक की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमिटियों का गठन किया जाएगा।

इस योजना की समय–सीमा वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर वित्तीय वर्ष 2029 (10 वर्ष) के लिए होगी।

'जल जीवन मिशन' से होगी ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति : मंत्री श्री कंषाना

भोपाल। पी.एच.ई. मंत्री श्री ऐंदल सिंह कंषाना ने विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पी.एच.ई. के राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव भी उपस्थित थे। श्री कंषाना ने कहा कि पेयजल के लिए संचालित एकल एवं समूह नलजल योजनाओं की सतत देखरेख की सुदृढ़ व्यवस्था की जाय। उन्होंने कहा कि आमजन के लिए निरंतर पेयजल सुलभ होता रहे यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की समुचित पेयजल व्यवस्था के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई ''जल जीवन मिशन'' का प्रदेश में सुनियोजित क्रियान्वयन किया जाये ताकि प्रत्येक परिवार को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। विभागीय चर्चा के दौरान मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि पेयजल योजना के और बेहतर संचालन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ संयुक्त बैठक कर सहयोग लिया जायेगा।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मलय श्रीवास्तव ने मंत्री श्री कंषाना एवं राज्य मंत्री श्री यादव को विभागीय संरचना, गतिविधियों, जल जीवन मिशन, राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, हैण्डपम्पों सहित एकल एवं समूह नलजल योजनाओं की विस्तृत जानकारी (पी.पी.टी) के माध्यम से दी। जल निगम के अधिकारियों ने भी निगम की योजनाओं के क्रियान्वयन, बजट उपलब्धता आदि के संबंध में भी अवगत कराया।

छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाने में मध्यप्रदेश अव्वल

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स ने दिया धन्यवाद, आत्मीय बातचीत से हुए खुश

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना में प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के हितग्राहियों को लाभान्वित करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। प्रदेश में अब तक 15 लाख 500 प्रकरण मंजूर हो चुके हैं और कुल 15 करोड़ 50 लाख की ब्याज मुक्त ऋण राशि स्वीकृत की गई है। योजना में 8 लाख 70 हजार 330 पथ विक्रेताओं ने पंजीयन करवा लिया है। इन पथ विक्रेताओं में से एक लाख 76 हजार विक्रेताओं को परिचय पत्र और वेंडर प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए हैं।

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के संकट ने सबसे अधिक छोटा–छोटा व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को प्रभावित किया लेकिन राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। इन्हें अपने रोजगार को चालू रखने और उसे बढ़ाने के लिए सहायता देने की योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम निधि) योजना के क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें मध्यप्रदेश अव्वल है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सब्जी का ठेला लगाने वाले, चाट की दुकान चलाने वाले, सिलाई कार्य से जुड़े वर्ग और चाय आदि की दुकान संचालित करने वाले लघु व्यवसायियों को योजना का अधिकाधिक लाभ दिया जाएगा ताकि ब्याज के बोझ से बचकर ये सभी अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें, परिवार की ठीक ढंग से गुजर बसर कर सकें। छोटा–छोटा व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार उन्हें पूरा सहयोग देगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रदेश के पथ विक्रेताओं से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा की गई आत्मीय बातचीत से स्ट्रीट वेंडर्स काफी खुश हुए अधिकांश ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को मामा कहकर ही संबोधित किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में योजना के अंतर्गत सभी पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स को परिचय पत्र देने की कार्रवाई पूर्ण की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना की निरंतर समीक्षा होगी। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही ग्रामीण स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी 10 हजार की ब्याज मुक्त सहायता देने की योजना संचालित की जा रही है। समय पर ऋण चुकाने पर अगले वर्ष दुगनी राशि अर्थात 20 हजार की राशि स्वीकृत की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कई बार छोटे व्यवसाय में लगे व्यक्ति की कर्ज चुकाते–चुकाते जिंदगी बीत जाती है। इस योजना में हितग्राही को ऋण राशि एक साल में लौटाने की सुविधा रहेगी और ब्याज न लगने से सबके व्यवसाय को संजीवनी मिलेगी। लोन की गारंटी सरकार वहन करेगी। बहुत से व्यवसाई जो व्यवसाय बंद कर चुके थे अब वे फिर से अपना काम–धंधा शुरू कर सकेंगे।

हितग्राहियों ने कहा सरकार ने दिया हमें बड़ा सहारा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न जिलों के योजना में लाभान्वित हितग्राहियों से बातचीत की। अधिकांश लाभांवित हितग्राहियों का यही मानना था कि उन्हें संकट के समय सरकार ने बड़ा सहारा दिया है अनूपपुर की श्रीमती पूजा राठौर सिलाई कार्य करती हैं। उन्होंने इसी साल जनवरी महीने में 4 नई मशीन खरीदकर सिलाई कार्य प्रारंभ किया था। कभी यह अंदाज नहीं था कि कोरोना वायरस संकट आ जाएगा। श्रीमती पूजा ने बताया कि उसका व्यवसाय बंद हो गया। जमा पूंजी भी खत्म हो गई और वह कर्जदार हो गई। इस बीच राज्य सरकार की जीवन शक्ति योजना में उसने 200 मास्क बनाए, जिससे उसे 2200 रुपए की राशि मिल गई। प्रधानमंत्री स्व निधि योजना में 10 हजार रुपए मिल जाने से वह फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर पा रही है।

आगर के श्री पंकज यादव चश्मे और पर्स आदि बेचने का कार्य करते हैं। उन्हें भी योजना में राशि मिली है और अब वे बहुत खुश हैं कि काम–धंधा ठीक तरह से चल सकेगा। भोपाल के श्री संतोष जोशी सब्जी का ठेला लगाते हैं। लॉकडाउन की अवधि में वे हताश हो गए थे। अब उन्हें आशा है कि प्रतिदिन कम से कम 300 रुपए की बचत हो सकेगी। भिंड के श्री गोपाल भी सब्जी का व्यवसाय करते हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनके कार्य को संचालित करने में अब दिक्कत नहीं आएगी।

दतिया जिले के भांडेर के निशू चौधरी चाट का ठेला लगाते हैं। इन्हें भी योजना में सहायता प्राप्त हुई है। रायसेन के लखन अहिरवार फल व्यवसाई हैं। इन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था और अब योजना का लाभ मिलने से पूरा परिवार खुश है कि गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। मंदसौर के श्री जयकुमार चाय का ठेला लगाते हैं। उन्हें भी परिवार की आर्थिक तंगी से मुक्ति मिली है। मुरैना के श्री बाथम पाव भाजी का ठेला लगाते हैं। उनका मानना है कि अब व्यवसाय परिवर्तित कर फल की दुकान शुरू करेंगे जिसमें उन्हें ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। मुरैना के श्री विष्णु राठौर ऋण मिल जाने पर अब फल और सब्जी का ठेला लगायेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में उनकी पोहे की दुकान थी। सरकार से मिली मदद से उन्हें काफी राहत मिली है उन्हें परिवार के लिए 3 माह का राशन भी मिला है। उज्जवला योजना में पत्नी के नाम रसोई गैस कनेक्शन और सिलेंडर मिल चुका है। अभी जून का राशन भी प्राप्त हो गया है। श्री विष्णु राठौर ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को भावुक होकर बताया कि उन्हें प्राप्त सहायता से बहुत खुशी मिली है और पूरा यकीन है कि गाड़ी लाइन पर आ जाएगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीतेश व्यास, आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव और अपर आयुक्त श्री स्वतंत्र सिंह उपस्थित थे।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

मध्यप्रदेश के 378 नगरीय निकायों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कोविड–19 के संकट में शहरी पथ व्यवसायियों का रोजगार प्रभावित होने पर उन्हें पुनः रोजगार से जोड़ने और स्थाई आजीविका का साधन उपलब्ध कराने के लिए योजना प्रारंभ की गई। भारत सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि(पीएम स्व निधि) योजना में शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रावधान किए हैं। ऐसे पथ विक्रेता जो 24 मार्च 2020 के पहले पथ विक्रेता रहे हो या कोरोना के कारण अन्य प्रदेश से अपने प्रदेश में लौट आए हो वे योजना में पात्र होंगे। शहरी क्षेत्र के नजदीक के ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेता जो शहर में कार्य करने आते हैं, वे भी योजना का लाभ ले सकेंगे। योजना में 1 साल के लिए 10 हजार की कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी जो पूरी तरह ब्याज मुक्त होगी। इस ऋण राशि पर आने वाले ब्याज अनुदान का 7 प्रतिशत भारत सरकार और शेष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर साल में अधिकतम 1200 का विशेष अनुदान भी प्राप्त होगा। समय पर राशि का भुगतान करने पर हितग्राही अधिकतम 20 हजार रुपए की कार्यशील पूंजी आगामी वर्ष में प्राप्त कर सकेगा। हितग्राही को ओवरड्राफ्ट और सीसी लिमिट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। हितग्राही को ऑनलाइन आवेदन और ऑनलाइन ऋण मंजूरी की सुविधा दी गई है। सिर्फ 50 रुपए के स्टांप पेपर पर अनुबंध करने के निर्देश हैं। केंद्र सरकार ने पीएम स्व निधि योजना पोर्टल 2 जुलाई 2020 को लांच किया जिसमें राज्य शासन के प्रस्ताव पर राज्य के पंजीकृत असंगठित कामगारों को भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने 6 जून 2020 को मुख्यमंत्री शहरी संगठित कामगार एकीकृत पोर्टल तैयार किया था इसमें प्रदेश के नगरीय निकायों के करीब पौने नौ लाख पथ विक्रेता रजिस्टर्ड हुए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश

- पथ विक्रेताओं को ऋण प्रदान करने में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए।
- पथ विक्रेताओं को ऋण राशि उपलब्ध करवाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उनके रोजगार के कार्य प्रारंभ हो।
- सभी पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र प्रदान किए जाएं।
- योजना की निरंतर समीक्षा की जाए।
- कोई भी पथ विक्रेता लाभ से वंचित न रहे, इसका लगातार अनुश्रवण हो।
- प्राप्त शिकायतों पर गंभीरता से कार्यवाही हो।
- अतः सभी अधिकारी, कर्मचारी मुस्तैद रहें।

सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखे, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे।

–अब्दुल कलाम

अपर आयुक्त श्री अरूण माथुर सहकारिता मंत्री के ओएसडी नियुक्त

भोपाल। राज्य शासन ने सहकारिता विभाग में पदस्थ अपर आयुक्त श्री अरूण माथुर को सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद भदौरिया की निजी स्थापना में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) नियुक्त किया है। अपर आयुक्त श्री माथुर आगामी आदेश तक अपने वर्तमान कार्य के साथ–साथ सहकारिता मंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के कार्यों को भी अतिरिक्त रूप से संपादित करेंगे।

ट्रांसफार्मर और मीटर का बेहतर प्रबंधन करें : ऊर्जा मंत्री श्री तोमर

ऊर्जा मंत्री ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा

भोपाल। ट्रांसफार्मर और मीटर का बेहतर प्रबंधन करें। सभी वितरण कम्पनियों के स्टोर का निरीक्षण करवायें। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा में दिये। श्री तोमर ने कहा कि मितव्ययता पर विशेष ध्यान दें।

श्री तोमर ने कहा कि शहरों में शत–प्रतिशत घरों में बिजली मीटर लगाये जायें। इसके साथ ही प्रतिमाह इनकी रीडिंग भी ली जाये। आकलित खपत के बिल नहीं दिये जायें। इससे जहाँ विद्युत उपभोक्ता संतुष्ट होगा, वहीं कम्पनी की आय भी बढ़ेगी।

90 दिन का लक्ष्य तय करें

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि बिजली से संबंधित हानियों (स्वेमे) को कम करने के लिये 90 दिन का लक्ष्य रखें। इस दौरान हर छोटी–बड़ी कमियों का विश्लेषण कर उन्हें दूर करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिये पेट्रोलिंग बढ़ायें। सभी स्तर के अधिकारी फील्ड में जायें। श्री तोमर ने कहा कि लापरवाह और काम नहीं करने वाले अधिकारी–कर्मचारी को वीआरएस दें।

श्री तोमर ने कहा कि स्टोर में जो सामग्री पड़ी है, उसे फील्ड में भेजें, सामग्री की जरूरत का आकलन बेहतर ढंग से करें। अनावश्यक सामग्री नहीं खरीदी जाये।

आपके मान–सम्मान में कमी नहीं आने देंगे

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि सभी लोग मिलकर उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएँ दें। उन्होंने कहा कि आपके मान–सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। श्री तोमर ने कहा कि कहीं खंभे टेढ़े हैं, तो कहीं तार झूल रहे हैं, ऐसी समस्याओं का त्वरित निराकरण करें। अधिकारियों–कर्मचारियों को बेहतर कार्य करने पर सम्मानित करें और लापरवाही पर दण्डित करें। बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान सचिव श्री आकाश त्रिपाठी, ओएसडी श्री एस.के. शर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

वन ग्रामवासियों की जीवन शैली बेहतर करने के होंगे प्रयास

वन मंत्री श्री विजय शाह द्वारा कार्यभार ग्रहण

भोपाल। कुंवर विजय शाह ने मंगलवार को मंत्रालय में वन मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि शासन वन ग्रामवासियों की समस्याओं का निराकरण करने के साथ उनको विकसित जीवन शैली से जोड़ने का प्रयास करेगा। श्री शाह ने सिवनी जिले के पेंच अभयारण्य के कर्माझिरी वन ग्रामवासियों के विस्थापन से संबंधित नस्ती पर हस्ताक्षर करने के दौरान विस्थापन कार्यवाही की विस्तृत जानकारी ली। प्रमुख वन सचिव श्री अशोक वर्णवाल और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राजेश श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

वन मंत्री श्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि प्रदेश के वन ग्रामों में रहने वाले लोग बेहतर जीवनयापन कर सके, इस दिशा में सार्थक पहल की गई है। प्रदेश के वन, वन्यप्राणी और वनवासियों को सुरक्षित रखने के हरसंभव प्रयास किये जायेंगे। नेशनल पार्क में बसे वनवासियों को अन्य ग्रामों में पुनः स्थापित कर इन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जायेगा। विस्थापन से इन्हें रोजगार के साथ बुनियादी सुविधाएँ भी मिलने लगेंगी। मंत्री श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2016 से 2018 के मध्य किये गये अथक प्रयासों का परिणाम है कि मध्यप्रदेश को एक बार फिर टाईगर स्टेट का दर्जा मिला है।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करें : मंत्री श्री डंग

विभागीय अधिकारियों की बैठक ली

भोपाल। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने कहा है कि अधिकारी लोगों के बीच नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में ठोस कदम उठाएँ। उन्होंने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काफी संभावनाएँ हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जनसाधारण को इस सिलसिले में जागरूक बनाया जाए।

मंत्री श्री डंग मंत्रालय में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा चलित पंपों में सरकार ने छूट दी है। शासकीय भवनों में भी सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली की खपत में काफी कमी आ सकती है। मंत्री श्री डंग ने अधिकारियों से विभिन्न जिलों में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के प्रति किसानों की दिलचस्पी की बाबत ब्यौरा लिया।

नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री सोलर पंप, कुसुम ''अ'' तथा सोलर रूफटॉप के बारे में भी जानकारी तलब की। बैठक में बताया गया कि जून 2020 तक मुख्यमंत्री सोलर पंप के तहत कुल 18 हजार 313 नग क्षमता स्थापित है।

मंत्री श्री डंग ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के संबंध में विभागीय अधिकारियों से भविष्य की विभागीय योजनाओं का ब्यौरा लिया। उन्होंने मंदसौर क्षेत्र में अस्पताल और कॉलेज भवन में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग किये जाने की पहल के बारे में भी चर्चा की। मंत्री श्री डंग ने कहा कि अधिकारी पूरी ताकत से इस क्षेत्र में काम करें, तो बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री डंग ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि में नवकरणीय ऊर्जा का उपयोग

काफी उपयोगी साबित होगा। बैठक में पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजना की क्षमताओं के सिलसिले में भी चर्चा हुई।

मंत्री श्री डंग ने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे मुख्यमंत्री सोलर पंप के लिये पंजीयन का कार्य शुरू करें। अगली बैठक में इस सिलसिले में जानकारी ली जायेगी कि संबंधित अधिकारियों द्वारा अपेक्षित पहल की गई है अथवा नहीं।

बैठक में प्रमुख सचिव नवकरणीय ऊर्जा श्री संजय दुबे तथा ऊर्जा विकास निगम के एम. डी. श्री दीपक सक्सेना एवं संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

कार्यभार ग्रहण करने के पहले मंत्री श्री डंग ने विधिवत् पूजा–अर्चना की।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने फसलों का लिया जायजा

कृषि अधिकारियों को दिये निर्देश

भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा जिले के बारंगा गाँव के खेतों में भ्रमण कर किसानों द्वारा लगाई गई सोयाबीन की फसल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कृषि अधिकारी और विभाग का मैदानी अमला किसानों के खेतों का भ्रमण करें तथा फसलों को कीटव्याधि से बचाने के लिए उचित सलाह दें। फसलों की अच्छी पैदावार के लिए किसानों को लगातार मार्गदर्शन देते रहें। ग्राम भ्रमण के दौरान मंत्री श्री पटेल ने खेत में ट्रैक्टर भी चलाया।

प्रदेश में अब हर गरीब को मिलेगा उचित मूल्य राशन

वन नेशन वन–राशन कार्ड की बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लिया बड़ा निर्णय

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के गरीब वर्ग के व्यक्तियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है, जिसके अनुसार प्रदेश के ऐसे 36 लाख 86 हजार 856 गरीब जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता पर्ची नहीं है, उन्हें भी पात्रता पर्ची जारी कर उचित मूल्य राशन प्रदाय किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 5 करोड़ 44 लाख 24 हजार उचित मूल्य उपभोक्ता हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में ''वन नेशन–राशन कार्ड'' संबंधी बैठक में कहा कि प्रदेश में अब हरेक गरीब को उचित मूल्य राशन मिलेगा। कोरोना काल में पता चला कि प्रदेश में बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं होने से उचित मूल्य राशन नहीं मिल रहा था। पहले तो प्रदेश में तुरंत उनके राशन की व्यवस्था की गई, साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए भी राशन की व्यवस्था की गई। अब ऐसे सभी 36 लाख 86 हजार गरीबों की पहचान कर ली गई है तथा उन्हें पात्रता पर्ची जारी करने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। अब ये सभी उचित मूल्य राशन उपभोक्ताओं के रूप में पंजीकृत हो जाएंगे तथा इन्हें अगस्त माह से उचित मूल्य राशन मिल सकेगा। प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब उचित मूल्य राशन से वंचित नहीं रहेगा।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि प्रदेश की सभी 25 हजार 490 उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीनों पर आधार दर्ज करने की सुविधा है। त्रुटिपूर्ण एवं अन्य के दर्ज आधार नंबर में संशोधन की सुविधा भी पीओएस में है। विक्रेता द्वारा राशन वितरण करते समय एवं घर–घर जाकर आधार सीडिंग का कार्य किया जा रहा है। समग्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय द्वारा भी आधार सीडिंग की सुविधा है। जिन हितग्राहियों का आधार पंजीयन नहीं है, उनको पंजीयन कराने के लिये अवगत कराया जा रहा है।

अभियान चलाकर करें आधार सीडिंग का कार्य

मुख्य सचिव श्री बैंस ने कहा कि वन नेशन–वन राशन कार्ड योजना के त्वरित क्रियान्वयन के लिए सभी उचित मूल्य हितग्राहियों की आधार सीडिंग का कार्य अभियान चलाकर पूरा किया जाए। सभी पात्र व्यक्तियों को जोड़े जाने एवं पात्रता पर्ची वितरण का कार्य तत्परता के साथ किया जाए।

व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता हैं।

–महात्मा गांधी

प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को अंतर राज्यीय पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्रदाय किया जाना है। इसके अंतर्गत उचित मूल्य दुकान का 100 प्रतिशत आटोमेशन तथा 100 प्रतिशत आधार सीडिंग की जानी है। इसकी समय–सीमा 31 दिसंबर तक है।

कपास-मक्का वाले क्षेत्रों में यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करें : मंत्री श्री पटेल

भोपाल। मंत्री श्री पटेल ने केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा से दूरभाष पर एक लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया उपलब्ध कराने के लिये चर्चा की। केन्द्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि एक सप्ताह में यूरिया की खेप मध्यप्रदेश को उपलब्ध करा दी जायेगी। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि पूर्व में हुई चर्चा अनुसार एक लाख 50 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया मध्यप्रदेश को उपलब्ध कराया जाना था। अब तक 43 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया प्राप्त हुआ है। शेष यूरिया की मात्रा शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाये।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने आज खरीफ की फसलों को दृष्टिगत रखते हुए यूरिया आपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने वरिष्ठ

कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया कि कपास और मक्का उत्पादक जिलों में यूरिया की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करें। मंत्री श्री पटेल ने गरोठ रैक प्वाइंट को भारत सरकार से शीघ्र चालू कराने के लिये फॉलोअप के निर्देश दिये।

खरीफ की फसलों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में यूरिया की उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा करते हुए छिन्दवाड़ा, खरगोन, खण्डवा, बड़वानी एवं अन्य जिलों में यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगामी सप्ताह से धान उत्पादक जिलों में भी यूरिया की माँग बढ़ेगी। उन क्षेत्रों में यूरिया की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम भण्डारण कराये जाने के निर्देश कृषि मंत्री ने दिये।

श्री सिलावट ने मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण किया

भोपाल। जल–संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर प्रमुख सचिव श्री अश्विन राय तथा मछुआ कल्याण संघ के संचालक श्री धीमान भी उपस्थित थे।

कार्यभार ग्रहण करने के बाद मंत्री श्री सिलावट ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग को रोजगार उन्मुख बनाया जाए। विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करना होना चहिए। मछली पालन विभाग से युवाओं और विशेषकर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। मछली पालन की योजना और उसके लाभ से लोगों को अवगत कराया जाए तथा लोगों में मछली पालन के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए।

मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि स्वरोजगार योजना का बड़ा अभियान चलाया जाये तथा विभाग की योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों को दिया जाए। केन्द्र प्रवर्तित योजना का लाभ लेने के लिए कार्य–योजना बनाकर भेजें और परम्पराओं से हटकर कार्य करें। मछुआ कल्याण की योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। मछली पालन के लाभ से लोगों को अवगत कराने के लिए फील्ड विजिट कराएँ। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।

प्रमुख सचिव श्री अश्विन राय ने बताया कि मछली पालन में कृषि से अधिक आय होती है। लगातार मछली पालन से लागत कम होती जाती है और इसमें लाभ बढ़ता है। विभाग की योजना में 60 प्रतिशत सब्सिडी अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को दी जाती है, शेष के लिए 40 प्रतिशत सबसिडी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा में विभागों की प्राथमिकताएं निर्धारित कीं

रोडमैप बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रीगणों से वन–टू–वन चर्चा कर विभाग की प्राथमिकताएं निर्धारित कीं। श्री चौहान ने कहा कि चर्चा में तय हुए बिन्दुओं पर विभाग अपना रोडमेप तैयार करें तथा समय–सीमा निर्धारित कर बिन्दुओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले माह पुनः विभागवार समीक्षा की जाएगी।

शासकीय कामकाज में होगा आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस का उपयोग

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सकलेचा को प्रदेश में सिंगल सिटीजन डेटाबेस तैयार कराने के निर्देश दिये है। प्रदेश में नागरिकों तथा उद्योगों को दी जा रही सेवाओं के लिए एकीकृत पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। शासकीय काम–काज में आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीक का उपयोग आरंभ करने के निर्देश भी दिए गए है। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रयास बढ़ाने के क्रम में उद्योग केन्द्रों की व्यवस्थाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से विश्व स्तरीय बनाने व साइबर सिक्यूरिटी की रणनीति बनाने का कार्य भी समय–सीमा में पूर्ण किया जाना है। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज से एम. एस.एम.ई. के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए जारी गतिविधियों की समीक्षा के निर्देश भी दिए गए।

स्वास्थ्य सेवाओं की पुख्ता रणनीति विकसित

मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी से चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की पुख्ता रणनीति विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला स्तर पर अस्पतालों तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और उनके स्तर में सुधार लाने के लिए कार्ययोजना विकसित करने के निर्देश दिए। चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री श्री विश्वास सारंग से वन–टू–वन चर्चा में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मेडिकल कॉलेजों की अधोसंरचना और सेवाओं को निरंतर बेहतरी के लिए कार्य करने की आवश्यकता बताई।

मंडी अधिनियम के संशोधित प्रावधानों को तत्काल लागू किया जाए

किसान कल्याण तथा कृषि विकास राज्य मंत्री श्री गिर्राज डण्डौतिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंडी अधिनियम के संशोधित प्रावधानों को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। श्री चौहान ने कहा कि शासकीय मंडियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुधार आवश्यक हैं। वन–टू–वन चर्चा में बीमा योजना के एंड–टू एंड कम्प्यूटराईजेशन, मोटे अनाज और फसल विविधीकरण के प्रोत्साहन और कृषि उत्पादों की उपयुक्त मार्केट लिंकेज स्थापित करने के कार्य को गति देने की आवश्यकता बताई।

महिला स्व–सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह सिसोदिया से चर्चा में जल संरक्षण कार्यों के क्रियान्वयन, मनरेगा तथा महिला स्व–सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार सृजन और च्डळैल् की सड़कों के संधारण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई।

विद्युत बिलों में दी गई छूट उपभोक्ताओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से चर्चा में विद्युत बिलों में दी गई छूट उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जारी कार्यवाही की लगातार समीक्षा की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि बिजली सब्सिडी सही व्यक्ति को मिले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। घरेलू तथा व्यवसायिक क्षेत्र में 24ग्7 बिजली तथा कृषि क्षेत्र में 10 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार प्रगति

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चर्चा के दौरान नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग को सौर ऊर्जा क्षेत्र में लगातार प्रगति तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की व्यवस्था की लगातार समीक्षा एवं कार्यप्रणाली का एंड–टू–एंड कम्प्यूटराइजेशन करने के निर्देश दिए।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्तर में सुधार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चर्चा के दौरान औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को प्रदेश में निवेश आमंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास करने, सिंगल विंडो का सही मायने में क्रियान्वयन करने, अनुमतियों की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं कम्प्यूटराईजेशन करने तथा औद्योगिक केंद्रों की व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने के लिए कहा।

प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का विस्तार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चर्चा के दौरान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार), नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा को एफपीओ (कृषक उत्पादक समूहों) को बढ़ावा देने, 2024 तक एनवीडीए/नर्मदा जल आधारित परियोजनाओं को पूरा करने तथा उद्यानिकी फसलों के लिए मार्केट लिंकेज स्थापित किये जाने के प्रयास करने के निर्देश दिए।

स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चर्चा के दौरान स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री, श्री इंदर सिंह परमार को ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता वाले स्कूल स्थापित करने एवं बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए बेहतर परिवहन व्यवस्था, हाईस्कूल /हायरसेकेंड्री स्कूलों की अधोसंरचना में सुधार करने के निर्देश दिए।

गौ–शालाओं के संचालन की रणनीति तैयार करना

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चर्चा के दौरान पशुपालन विभाग, सामाजिक न्याय विभाग मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल को पशुपालन से किसानों की आय कैसे बढ़े इसकी रणनीति बनाने, दुग्ध उत्पादक कृषकों को केसीसी प्रदान करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण की लगातार समीक्षा करने, दिव्यांगों की विशेष आवश्यकताओं के लिए सी.एस.आर. (कंपनियों का सीएसआर मद) से प्रदेश में विश्वस्तरीय केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए।

उच्च शिक्षा में सुधार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चर्चा के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव को प्रदेश में कम से कम एक विश्वविद्यालय और 5 महाविद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर की प्रथम 100 संस्थाओं में लाने की रणनीति बनाने के निर्देश दिए।

जल जीवन मिशन को लागू करना/योजनाएं स्वीकृत कराना

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चर्चा के दौरान लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव को ग्रामीण समूह नल–जल योजनाओं (जल निगम) का क्रियान्वयन तथा सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल घर–घर में उपलब्ध हो इसकी रणनीति बनाने (जल जीवन मिशन) के निर्देश दिए।

सड़कों का विश्वस्तरीय संधारण/निर्माण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चर्चा के दौरान लोक निर्माण राज्यमंत्री श्री सुरेश धाकड़ को ष्चंबल प्रोग्रेस वेष परियोजना की लगातार समीक्षा, भवन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता /समयसीमा में पूर्ण किए जाकर लगातार समीक्षा, निजी क्षेत्र के सहयोग से बड़ी परियोजनाओं की परिकल्पना करना तथा सड़क निर्माण कार्यों की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए।

आयुष व्यवस्था में सुधार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समीक्षा के दौरान आयुष (स्वतंत्र प्रभार) जल संसाधन राज्यमंत्री श्री रामकिशोर (नानो) कांवरे को आयुष अस्पताल की व्यवस्था में सुधार तथा आयुष की सभी विधाओं के उपचार को घर–घर तक पहुंचाने की रणनीति बनाने के निर्देश दिए।

पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्तियों के वितरण की समीक्षा करना

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समीक्षा के दौरान पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्क्ड जनजाति कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, श्री रामखेलावन पटेल को मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन, जल संरक्षण कार्यों का क्रियान्वयन, महिला स्व–सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार के अवसर, मनरेगा के माध्यम से टिकाऊ अधोसंरचना का विकास तथा पीएमजीएसवाई की सड़कों का सुधार आदि के निर्देश दिए।

किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर मिलेंगे बाँस के उन्नत पौधे

भोपाल। राष्ट्रीय बाँस मिशन के तहत प्रदेश के किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उन्नत गुणवत्ता वाले बाँस के पौधे उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्रति पौधा 240 रूपये लागत वाला यह पौधा किसानों को 120 रूपये में मिलेगा। राशि अनुदान का वितरण तीन वर्षो तक किया जायेगा। पहले साल में 60 रूपये प्रति पौधा, दूसरे में 36 रूपये और तीसरे साल में किसानों को 24 रूपये प्रति पौधा अनुदान मिलेगा। पहले वर्ष में रोपित सभी पौधों पर अनुदान दिया जायेगा। दूसरे साल 80 प्रतिशत पौधों की जीवितता पर (मृत पौधा बदलाव सहित) और तीसरे साल शत–प्रतिशत पौधों की जीवितता (मृत पौधा बदलाव सहित) सुनिश्चित करने पर अनुदान दिया जायेगा।

किसानों की आय बढ़ने के साथ बाँस उत्पादन में होगी बढोत्तरी

योजना से प्रदेश में अच्छी गुणवत्ता वाले बाँस का उत्पादन बढ़ने के साथ ही किसानों को अच्छा मूल्य मिलने से अतिरिक्त आय होगी। बाँस आधारित शिल्पकारों और बाँस उद्योग को पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की आपूर्ति की जा सकेगी। किसान अपनी कृषि भूमि, मेड़ आदि पर अपनी इच्छा अनुसार बाँस की प्रजातियाँ लगाने के लिये स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन किसानों को यह पौधे मध्यप्रदेश राज्य बाँस मिशन द्वारा मान्यता प्राप्त रोपणियों या भारत सरकार के बायोटेक्नोलोजी विभाग से एन.सी.एस.–टी.सी. पी. प्रमाण पत्र प्राप्त टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता पूर्ण पौधों को क्रय कर लगाना होगा। पौधा क्रय का भुगतान किसान द्वारा रोपणी/लेब को किया जायेगा।

वनमण्डलाधिकारियों को देना होगा आवेदन

योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान संबंधित वनमण्डलाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिकारी बाँस मिशन द्वारा आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के सीमा के अनुसार हितग्राही का चयन करेंगे। चयन में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला कृषको को प्राथमिकता दी जायेगी। न्यूनतम रोपण 375 से 450 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाने का प्रावधान है। पौधों का अन्तराल किसान खुद तय करेंगे। बाँस पौधो के बीच कृषि फसलों की अन्तरवर्ती फसलें भी ली जा सकेगी।

प्रत्येक पात्र आदिवासी को मिले वनाधिकार पट्टे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वनाधिकार दावों के निराकरण संबंधी बैठक ली

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को उनका जायज हक दिलवाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में पूर्व में बड़ी संख्या में आदिवासियों के वनाधिकार पट्टों के दावों को अमान्य किया गया है, जो ठीक नहीं है। अधिकारी पूरी संवेदना एवं तत्परता के साथ एक–एक दावे का परीक्षण करें तथा प्रत्येक पात्र आदिवासी को वनाधिकार पट्टा दिलवाना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में आदिम जाति कल्याण विभाग की बैठक में वनाधिकार दावों के निराकरण की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में वन मंत्री श्री विजय शाह तथा उमरिया से वी.सी द्वारा आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह शामिल हुए। इसके साथ ही बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण तथा प्रमुख सचिव वन श्री अशोक वर्णवाल उपस्थित थे।

आदिवासियों के बीच स्वयं जाऊँगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे स्वयं आदिवासियों के बीच जाकर इस बात का परीक्षण करेंगे कि किसी पात्र आदिवासी का वनाधिकार पट्टे का दावा निरस्त तो नहीं किया गया। यदि ऐसा पाया गया तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मंत्री श्री विजय शाह एवं सुश्री मीना सिंह से कहा कि वे भी जाकर वनाधिकार दावों संबंधी परीक्षण करें।

ग्राम वन अधिकार समितियों द्वारा 92 हजार 470 दावे निराकृत

बैठक में बताया गया कि ग्राम वन अधिकार समितियों द्वारा अभी तक लंबित एक लाख 67 हजार 108 दावों में से 92 हजार 470 दावों का निराकरण किया गया है। इन दावों में से 36 हजार 241 (39.19 प्रतिशत) दावों को मान्य किया गया है तथा 56 हजार 229 (60.8 प्रतिशत) दावों को अमान्य किया गया है। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिए गए कि एक–एक दावे का पुनः परीक्षण किया जाए। कोई भी पात्र आदिवासी वनाधिकार पट्टे से वंचित नहीं रहना चाहिए।

हजारों सम्बन्ध रखना कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। चमत्कार यह है की आप एक ऐसा सम्बन्ध बनाये जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब हजारों आपके खिलाफ हो जाये।

–शिवानी दीदी

हरे मानसून में पीले मेंढकों से भरा तालाब बना कौतूहल का केन्द्र

भोपाल। नरसिंहपुर जिले के आमगांव में एक तालाब में अचानक पीले नीबू रंग के मेंढकों की उपस्थिति स्थानीय लोगों के कौतूहल और आकर्षण का केन्द्र बन गया। यहां बड़ी संख्या में अचानक बहुत से पीले मेंढक दिखे जिनके गले में गहरे नीले रंग की गुब्बारे की आकृति (वोकल सेक) उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह भारतीय नर बुलफ्रॉग है, जो अक्सर प्रजनन काल में अपना रंग बदलकर चमकीले पीले रंग के हो जाते है।

सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री जीतेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि मध्यप्रदेश में यह मेंढक मानसून के दौरान कभी–कभी देखे जाते हैं। उन्होंने तकरीबन 6–7 साल पहले सतपुड़ा टाईगर रिजर्व में इन्हें देखा था। पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री रवीन्द्र सक्सेना ने बताया कि यह मेंढक सामान्य रूप रंग के ही होते है परंतु मानसून में प्रजनन काल के दौरान मादा मेंढक को रिझाने इनके पिगमेंट का रंग हल्दी जैसा पीला हो जाता है। वहीं इनके गले की वोकल सेक भी गहरे नीले रंग की हो जाती है। यह नजारा भारत के अलावा बॉग्लादेश, म्यामार पाकिस्तान में भी कहीं–कहीं दिखता है। भारत में जहां कम वर्षा होती है, वहां कभी–कभी यह नजारा देखने को मिल जाता है। इस साल नरसिंहपुर में काफी कम वर्षा हुई है।

जैव विविधता बोर्ड के सदस्य श्री श्रीनिवास मूर्ति ने बताया कि कुछ दिनों बाद यह वापस पीले रंग से सामान्य रंग में आ जाते है। इंडियन बुल फ्रॉग भारत के तालाब, पोखर, नाले आदि में पायी जाने वाली आम प्रजाति है। कई बार कम वर्षा और तापमान बढ़ने वाले इलाकों में यह आम तौर पर गहरे हरे रंग के मेंढक प्रजनन काल में गहरे पीले रंग का रूप धारण कर लेते हैं। भारतीय बुलफ्रॉग अपना ज्यादातर समय जमीन पर भोजन की तलाश बिताते हैं। जो उनके मुँह में समा सके ऐसी किसी भी चीज जैसे अन्य मेंढक, चूहे, छोटे पक्षी, साँप आदि को खाते हैं।

उल्लेखनीय है कि मेंढक पृथ्वी पर ऐसे पहले उभयचर माने जाते हैं, जो जमीन और जल दोनों में रहकर कीड़े–मकोडों को खाकर पर्यावरण संतुलन बनाये रखने में मदद करते हैं। जल और पृथ्वी दोनों जगह की जैव–विविधता आहार श्रृंखला बनाये रखने में इनका अति महत्वपूर्ण योगदान है।

उद्यानिकी राज्यमंत्री श्री कुशवाह ने की विभागीय समीक्षा

वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र में दौरा कर योजनाओं की जिला स्तर पर समीक्षा के दिए निर्देश

भोपाल। उद्यानिकी एंव खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार) एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने मंत्रालय में उद्यानिकी विभागीय समीक्षा बैठक में योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि विभाग की योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिये सरलीकृत प्रचार सामग्री तैयार करें, जिससे किसानों को योजनाओं की जानकारी आसानी से समझ में आयें और वे उनका लाभ लेने के लिये आगे आ सकें। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे जिलों में जाकर योजनाओं की समीक्षा करें और किसानों से भी सम्पर्क करें। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये कि पात्र हितग्रहियों को योजनाओं के प्रावधान अनुसार लाभ प्राप्त हो सकें। योजनाओं की सतत् समीक्षा की जाये जिन जिलों में आवंटन प्रदाय किया जा रहा है उसका व्यय समय–सीमा में हो।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि ''सेंन्ट्रल ऑफ ऐक्सीलेंस'' (वेजीटेविल) नूराबाद जिला मूरैना के भारत सरकार से स्वीकृत प्रस्ताव अनुसार कार्य करने के लिए एक सप्ताह की समय–सीमा में निविदा जारी की जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत योजनाओं के संचालन के लिए क्लस्टरों का चयन विकासखण्ड के अधिकारियों से फसलवार रकबे की जानकारी प्राप्त कर तैयार करायें। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि कुछ जिलों में क्लस्टरों में उद्यानिकी फसलों के नवीन क्लस्टर तैयार हुये हैं। इन क्लस्टरों में अन्य जिलों के क्षेत्र जैसे– दतिया के विकासखंण्ड सेवड़ा में लहसून की खेती, ग्वालियर जिले के बरही विकासखण्ड में मटर की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है इनको भी सम्मिलित किया जाय।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि शिवपुरी जिलें में टमाटर फसल उत्पादन एवं प्रसंस्करण के लिए किसानों की कार्यशाला आयोजित कर उन्हें जानकारी दी जाकर प्रेरित किया जायें। उन्होंने कहा कि विभाग संचालित लगभग 300 नर्सरियां को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मनरेगा, एवं विभागीय मद से उन्नत किया जाये जिससे प्रदेश के किसानों को उचित मांपदण्ड के फलदार पौधे एवं विभिन्न फसलों के मानक स्तर पर बीज प्राप्त हो सकें।

बैठक में प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा विभाग में संचालित समस्त योजनाओं, वित्तीय व्यवस्था एवं स्थापना संबंधी जानकारी दी। आयुक्त उद्यानिकी द्वारा विभाग की समस्त योजनाओं का पी.पी. टी. के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया गया। जिसमे आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत विभाग की ओर से तैयार किये गये प्रस्ताव सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (MFE) का इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक और कैपिसिटी बिल्डिंग को मजबूत करने के उपाय, हर्बल खेती का संवर्धन, मधुमख्खी पालन पहल आदि पर विस्तार से जानकारी दी गई।

किसानों की एक-एक इंच भूमि तक पानी पहुंचाने के प्रभावी प्रयास करेंगे

नाबार्ड द्वारा मध्यप्रदेश के लिए 1425 करोड़ रूपये की नई सिंचाई परियोजना स्वीकृत

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विजनरी लीडर और मैन ऑफ आइडिया है। उन्होंने कोविड की चुनौती को अवसर में बदला है तथा नए आत्मनिर्भर भारत का मंत्र एवं संकल्प लिया है। हम उसे पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाएंगे। इसके लिए खेती, किसान एवं गाँवों के अधिकाधिक विकास की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश में सिंचाई क्षमताएं बढ़ाने के लिए विशेष कार्य हुए हैं। गत वर्षों में हमने प्रदेश में सिंचाई क्षमता को 7.5 लाख हैक्टेयर से 42 लाख हैक्टेयर तक पहुंचाया है, इसमें नाबार्ड का महत्वपूर्ण योगदान है। आगामी समय में हम प्रदेश में किसानों की एक–एक इंच भूमि तक पानी पहुंचाने के प्रभावी प्रयास करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि नाबार्ड द्वारा मध्यप्रदेश के लिए 1425 लिफ्ट इरीगेशन को स्वीकृति दी गई है। साथ ही अन्य परियोजनाओं के लिए 4 हजार करोड़ का ऋण भी स्वीकृत किया है। इसके लिए मैं नाबार्ड की पूरी टीम का पूरे हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में नाबार्ड के 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के महिला स्व–सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संघों के प्रतिनिधियों, प्रगतिशील किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया, महाप्रबंधक नाबार्ड डॉ. डी.एस. चौहान , मुख्य सचिव श्री

इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज गोविल आदि उपस्थित थे।

24 प्रतिशत तक कृषि विकास दर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश ने कृषि विकास में 24 प्रतिशत तक विकास दर हासिल की है। इसका एक प्रमुख कारण सिंचाई के क्षेत्र में विशेष प्रयास है। इस विकास दर को हासिल करने में नाबार्ड का विशेष सहयोग रहा है। नाबार्ड द्वारा कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं कृषि अधोसंरचना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है।

स्व–सहायता समूह बनाएंगे लोकल को वोकल

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में स्व–सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। सरकार अब इन्हें 4 प्रतिशत ब्याज दर पर आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराएगी। नाबार्ड की ई–शक्ति योजना पर पूरा अमल किया जाएगा। महिला स्व–सहायता समूह लोकल को वोकल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

आपकी चादर मुझे भी देखना है

मुख्यमंत्री श्री चौहान वी.सी. के माध्यम से महिला स्व–सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संघों के प्रतिनिधियों, प्रगतिशील किसानों से बातचीत की। रतलाम जिले की गंगा स्व–सहायता समूह की छपली बाई ने बताया कि उनका समूह ब्लॉक प्रिंटिंग, पंजाबी सूट बनाने, चूड़ी निर्माण आदि का कार्य करता है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी चादर की बहुत तारीफ होती है मुझे भी आपकी चादर देखनी है। इस पर छपली बाई ने प्रसन्न होकर मुख्यमंत्री को अपनी ब्लॉक प्रिंटिंग से बनाई चादर दिखाई। मुख्यमंत्री ने कार्य की सराहना की। उन्होंने संगम स्व–सहायता समूह देवास की श्रीमती नंदिनी वर्मा, दुर्गा स्व–सहायता समूह धार की धापू बाई तथा ओम जय जगदीश हो स्व–सहायता समूह की उमा रजक से भी बातचीत कर उनके स्व–सहायता समूहों की गतिविधियों की जानकारी ली।

71.69 लाख का वार्षिक टर्न ओव्हर

मुख्यमंत्री श्री चौहान को रेवा किसान उत्पादन संगठन सीहोर के श्री प्रकाश मीना ने बताया कि उनका संगठन जैविक खेती, बीज उत्पादन, सब्जी उत्पादन, दूध संग्रहण, मवेशी उपलब्ध कराने का कार्य करता है तथा उनका वार्षिक टर्न ओव्हर 71.69 लाख रूपये है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्य की सराहना की।

देवास मॉडल देशभर में प्रसिद्ध

देवास के कृषि विशेषज्ञ डॉ. सुनील चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिले में रूफ वॉटर हारवेस्टिंग तकनीक को विकसित किया गया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता एवं भू–जल स्तर वृद्धि में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारा देवास मॉडल देशभर में प्रसिद्ध है।

2381 लाख की अनुदान सहायता परियोजनाओं का शुभारंभ किया

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा नाबार्ड की 2381.69 लाख रूपये की अनुदान सहायता परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनसे प्रदेश के 10.82 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इनमें मुख्यतरू स्व–सहायता समूहों संबंधी ई–शक्ति परियोजना (प्रदेश के सभी जिलों में) 1587 लाख, प्रवासी मजदूरों के लिए आजीविका कार्यक्रम 275.67 लाख, वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन कार्यक्रम 321.89 लाख, कृषि उत्पादक संघ, वाटरशेड परियोजना 196.89 लाख रूपये की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों के रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र के 5 मॉडल प्रोजेक्ट्स और प्रदेश में नाबार्ड के योगदान की किताबों का विमोचन भी किया।

एच.डी.एफ.सी बैंक की एफएमएस प्रणाणी का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा एच. डी.एफ.सी बैंक की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) द्वारा विकसित स्वयं सहायता समूहों के लिए वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (FMS) का शुभारंभ भी किया।

गत 10 वर्षों में एक लाख करोड़ के कार्य

नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती टी.एस. राजी गैन ने वी.सी. के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में नाबार्ड कृषि रोजगार, कृषि अधोसंरचना विकास आदि के क्षेत्र में कार्य कर रही है। गत 10 वर्षों में लगभग एक लाख करोड़ के कार्य किए गए हैं।

कृषि विकास दर में मध्यप्रदेश निरंतर आगे

नाबार्ड के अध्यक्ष श्री जी.आर. चिंताला मुंबई से वी सी में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि गत 15 वर्षों में मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर 10 प्रतिशत से भी काफी अधिक रही है, जबकि देश की 4 प्रतिशत के लगभग रही। मध्यप्रदेश में सिंचाई सेवाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इसके लिए मध्यप्रदेश बधाई का पात्र है।

मंत्री श्री अरविंद भदौरिया ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग की समीक्षा की

सीएम हेल्पलाईन में 97% आवेदन निराकृत

भोपाल। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद भदौरिया ने मंत्रालय में लोक सेवा प्रबंधन विभाग से संबंधित कार्यों व गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने लोक सेवा केन्द्रों तथा सी. एम. हेल्पलाइन को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिये। मंत्री श्री भदौरिया ने कहा कि कॉल सेन्टर में मुख्यमंत्री के संदेश व शासकीय योजनाओं से संबंधित अलग–अलग विषयों पर आधारित कॉलर ट्यून तैयार कराकर उपयोग की जाये ताकि शासकीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार भी हो सके।

प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी ने बताया कि नागरिक सेवा प्रदाय प्रणाली को बेहतर बनाने, लोक सेवा गारंटी क्रियान्वयन, सेवा प्रदाय के सरलीकरण, नागरिक शिकायतों के निराकरण के उद्देश्य से विभागान्तर्गत वर्ष 2013 में राज्य लोक सेवा अभिकरण की स्थापना की गई थी। बैठक में अभिकरण की संरचना, सामान्य निकाय व शासी समिति की संरचना के अलावा अभिकरण के स्वरूप के संबंध में भी पॉवर–प्वाइंट प्रेजेनटेशन के माध्यम से अवगत कराया गया।

बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लोक सेवा केन्द्रों द्वारा प्रदाय की जा रही नागरिक सुविधाओं, समाधान एक दिवस, सीएम हेल्पलाईन, एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर से भी संबंधित गतिविधियों से अवगत कराया गया। विभाग द्वारा नागरिक सुविधाओं की बेहतरी के लिये दी जा रही प्रमुख सेवाओं की भी जानकारी दी गई।

बैठक में बताया गया कि सीएम हेल्पलाईन के प्रारंभ से लेकर अब तक कुल 1.16 करोड़ लगभग शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1.12 करोड़ से अधिक शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। इस प्रकार कुल प्राप्त शिकायतों के 97 प्रतिशत का निराकरण हो चुका है। उल्लेखनीय है कि निराकृत मामलों में से 62 प्रतिशत मामले संतुष्टिपूर्ण निराकृत हुए हैं।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।